दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–22)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

GSM (M-I)-2422

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Arun Kumar **Mobile Number:**

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:**

Center & Date: Delhi (06/sep/2024) **UPSC Roll No. *(If allotted)*:** 5417292

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

drishti | दृष्टि The Vision

1. न्यायिक स्वतंत्रता की संवैधानिक प्रत्याभूति लोकतंत्र के अस्तित्व का मूल है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

The constitutional guarantee of judicial independence is fundamental to the existence of a democracy. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है (अब्राहम लिंकन)

स्वतंत्र लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की पहली शर्त है

न्यायिक स्वतंत्रता का महत्व —

- लोकतंत्र में जनविश्वास बनाये रखने हेतु
- कार्यकारी व विधायी शक्तियों पर नियंत्रण रखने हेतु (उदा० न्यायिक समीक्षा)
- लोगों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु (उदा० ~~अनु~~ 32 द्वारा रिटों का प्रावधान)
- संघीय ढांचा बनाये रखने हेतु (उदा० अनु० 127 सुप्रीम कोर्ट की अनन्य मूल क्षेत्राधिकार)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

न्यायिक स्वतंत्रता हेतु संवैधानिक प्रावधान

1). संविधान की सर्वोच्चता
2). न्यायिक समीक्षा के प्रावधान
3). Art. 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण
4) न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका हस्तक्षेप की अनुपस्थिति
(उदा० कॉलेजियम द्वारा न्यायिक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा)
5). न्यायधीशों के आचरण पर संसद में रोक
6) सेवा शर्तें व कार्यकाल
① न्यायधीशों पर महाभियोग की कठिन प्रक्रिया
② भारत की संचित निधि पर न्यायधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन
③ सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं
④ न्यायालयों को अवमानना की व्यापक शक्ति

अतः भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की जीवंत वाहक व रक्षक है।

drishti | दृष्टि The Vision

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) भारत में हाशिये पर स्थित समुदायों को निशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का प्रभावी अंतरण सुनिश्चित करता है। संपुष्ट कीजिये। (150 शब्द) 10

The National Legal Services Authority (NALSA) ensures the effective delivery of free legal aid services to marginalized communities in India. Substantiate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुलभ कराने हेतु तथा कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को प्राप्त करने हेतु DPSP के अनुच्छेद 39(A) द्वारा वर्ष 1987 में (NALSA) के निर्माण का प्रावधान किया गया था

NALSA में निशुल्क न्याय प्राप्त करने वाले समुदाय

1) SC/ST/दिव्यांगजन
2). महिला, बुजुर्ग व्यक्ति
3). औद्योगिक श्रमिक व कामगार
4). BPL रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीब समुदाय
5) तस्करी तथा बलात्कार यौन हिंसा के पीड़ित
6) साम्प्रदायिक हिंसा, बाढ़, आपदा से पीड़ित समुदाय

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

NALSA व्यापक न्याय की अवधारणा को न्यायिक सक्रियता (PIL) से क्रियान्वित करता है।

अतः वंचितों तक न्याय की सुलभ व निःशुल्क पहुंच ही लोकतंत्र का मूल आधार है। इस दिशा में NALSA का गठन प्रभावी समाधान है।

drishti | दृष्टि The Vision

3. भारत में राज्य पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को पर्याप्त कार्यात्मक और वित्तीय सशक्तीकरण प्रदान करने में असहयोगशील प्रतीत होते हैं। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

States in India appear unwilling to grant Panchayati Raj Institutions (PRIs) adequate functional and financial empowerment. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में (DPSP) के अनुच्छेद (40) के अधिदेश की पूर्ति हेतु भारतीय संविधान में भाग 9 तथा 11 वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

हाल ही में RBI की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता" रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। जिसमें स्थानीय निकायों में वित्तीय संसाधनों की कमी को रेखांकित किया गया

PRI का महत्व –
- तृणमूल स्तर के शासन भागीदारी
- स्थानीय समस्याओं को सामुदायिक भागीदारी द्वारा सुलझाना
- लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण द्वारा सहभागिता मूलक प्रशासन की स्थापना
- योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन

PRI का कार्यात्मक और वित्तीय सशक्तीकरण।

↳ 73वें संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग को

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पंचायती राज्य संस्थाओं के वित्त की पूर्ति का दायित्व सौंपा गया

2). राज्यों को वित्तिय शक्तियां प्राप्त है, राज्यों द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को वित्तीय शक्तियों का स्थानांतरण न किया जाना

पंचायती राज्य संस्थाओं के वित्तीय स्रोत
- केंद्र व राज्यों के अनुदान
- राज्य व केंद्र योजनाओं द्वारा वित्त पोषण
- स्थानीय कर
  - आवास
  - जल
  - सिंचाई
  - मेला, बाजार आदि

आगे की राह
- राज्यों द्वारा PRI संस्थाओं को वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण
- NCRWC आयोग की सिफारिशें लागू करना → (राज्य वित्त आयोग में पंचायतों का भागीदारी बढ़ाना)
- स्थानीय वित्तीय स्रोतों को बढ़ाना (उदा - गांव में सरकारी भवनों के उपयोग संबंधी किराया, स्वच्छता कर आदि।

अतः पंचायती राज्य संस्थाएं भारत में भागीदारी लोकतंत्र की पहचान है।

drishti | दृष्टि The Vision

4. संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश तथा भारतीय दृष्टिकोण में समानताएँ और विभिन्नताएँ दोनों ही देखने को मिलती हैं। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

The British and Indian approaches to parliamentary sovereignty exhibit both similarities and differences. Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में अनेकों संवैधानिक प्रावधानों को ब्रिटिश संसदीय परम्परा से लिया गया है किंतु भारत में संविधानवाद को ही प्रमुखता दी गई है।

ब्रिटिश तथा भारतीय संसदीय व्यवस्था में समानताएं

1) प्रधानमंत्री का पद.

2. राष्ट्रपति व क्राउन का नाममात्र प्रतिनिधित्व

3). विधायिका व कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था

4). मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा

अंतर

भारत	ब्रिटेन
(1) लिखित संविधान ↓ कार्यपालिका के विधान	1) अलिखित संविधान ↓ संसदीय परम्पराऐं
2). भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित	- परम्परागत पद (क्राउन)
3). संविधानवाद व संविधान की सर्वोच्चता।	- संसदीय सम्प्रभुता।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

4) भारतीय प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा से	ब्रिटिश PM सिर्फ कॉमन सभा से

अतः भारत तथा ब्रिटेन में 'पार्लियामेण्ट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट' को अपनाया गया है किंतु दोनों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अंतर है।

5. राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी विधायी कार्य में शिष्टाचार और अपक्षपात के सातत्य के साथ-साथ सुदृढ़ लोकतांत्रिक प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने के लिये ज़िम्मेदार होते हैं। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द) 10

State legislature presiding officers are responsible for upholding decorum and impartiality in legislative work, as well as facilitating sound democratic practices. Explain. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के भाग VI में केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था की तरह राज्य विधानमंडल तथा विधानपरिषद का प्रावधान है। विधानमंडल की अध्यक्षता 'राज्य विधानसभा' स्पीकर द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमंडल पीठासीन अधिकारी की भूमिका व कार्य

1. विधायी कार्यों में शिष्टाचार व निष्पक्षता बनाए रखना
2. 'सदन की गरिमा' हेतु सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखना
3. 'धन विधेयकों' का निर्धारण करना
4. सदन के अंदर संविधान का संरक्षक व व्याख्याकर्ता।
5. अल्पसंख्यक व कम सदस्यों वाले सदस्यों को पर्याप्त अवसर देना

हालांकि हाल ही में मध्यप्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद की निष्पक्षता पर सवाल उठाये गए हैं

1). अध्यक्ष द्वारा सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने हेतु 'दलबदल विधेयक' पर समय से कार्यवाही न करना

2) विपक्षी दलों को सदन से बाहर करना (उदा० बिहार विधान सभा)

3). साधारण विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित करना (उदा० उ०प्र० विधानसभा में "धर्मांतरण बिल"

सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष पद की गरिमा बनाये रखने हेतु (कीशम सिंह Vs मणिपुर राज्य 2023) में यह निर्देश दिया की 3 माह के अंदर अध्यक्ष को दल बदल पर निर्णय लेना चाहिए।

अतः भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में अध्यक्ष का महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है

6. भारत के विकास में एक बड़ी चुनौती मानव संसाधन विकास पर अपर्याप्त ध्यान देना है। इस अपर्याप्तता को दूर करने संबंधी उपायों के सुझाव प्रदान कीजिये। (150 शब्द) 10

A major challenge in India's development is the insufficient focus on human resource development. Suggest measures to address this inadequacy. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल ही में जारी UNDP के मानवविकास सूचकांक में भारत को 126वीं रैंक प्राप्त हुई है। भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी खराब है।

भारत के विकास में निम्न मानव विकास एक चुनौती बना हुआ है :

① शिक्षा व स्वास्थ्य में निम्न स्तर

(उदा०
- 77% आबादी साक्षर (2011 जनगणना)
- → स्वास्थ्य
  - मातृ मृत्युदर 97
  - शिशु मृत्युदर 26 } NHFS(5)
- → स्वास्थ्य
  - → 1/3 मोटापा भारत में
  - → विश्व की डीबी राजधानी
  - → 57% महिलाएं एनीमिया पीड़ित

(2) निर्धनता का दुष्चक्र भी निरंतर

निर्धनता → निम्न शिक्षा/स्वास्थ्य → निम्न कौशल → बेरोजगारी → निर्धनता

(vicious cycle of poverty)

(3) कौशल विकास निम्न

(NSSO के आंकड़ों के अनुसार 44% ग्रेजुएट ही रोजगार(योग्य))

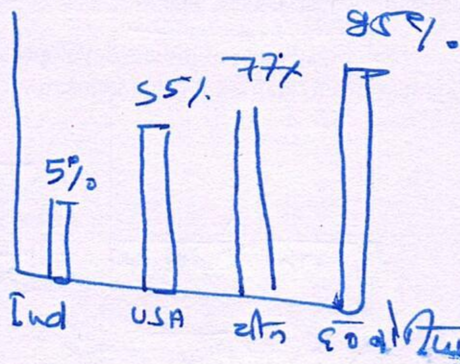

(4) शिक्षा, स्वास्थ्य पर घटता सरकारी बजटीय व्यय

- शिक्षा पर - 2.5% (NEP 2020 6% अनुमानित)
- स्वास्थ्य पर 2.1% (आउट ऑफ पॉकेट व्यय 47%)

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास में व्यय बढ़ा कर (3-4%) तक GDP में वृद्धि कर सकता है

उपाय
- → शिक्षा स्वास्थ्य पर बजटीय व्यय बढ़ाना (उदा० सत्यार्थी बजट)
- → कल्याण से सशक्तिकरण की ओर बढ़ना
- → रोजगार गहन उद्योगों का विकास (उदा० FPI, वस्त्र उद्योग, IT उद्योग, मत्स्यन)
- → कौशल विकास पर बल देना
- → महिला सशक्तिकरण (SHGs का विकास)
- → नोबेल अर्थशास्त्री - अभिजीत बनर्जी का कल्याण आधारित दृष्टिकोण
- → अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण

अतः भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना उचित मानव विकास से ही प्राप्त कर सकता है

drishti | दृष्टि The Vision

7. भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रमुख बाज़ार स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The Competition Commission of India plays a crucial role in preventing the misuse of dominant market positions by multinational companies in India. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने हेतु "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग" का गठन एक संविधिक संस्था के रूप में किया गया है।

MNCs द्वारा बाजार स्थिति का दुरुपयोग
- एकाधिकार द्वारा प्रतिस्पर्धा समाप्त करना
- अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाना
- फिक्सिंग प्रक्रियाओं द्वारा अपना बाजारांश बढ़ाना
- ग्रीनवाशिंग प्रथाओं द्वारा ग्राहकों को भ्रमित करना
- ई कॉमर्स संस्थाओं द्वारा मूल्य गिरावट छोटे व मझोले दुकानदारों से अपरस्वाधिकार

CCI की भूमिका
1. बाजार में कार्टेलाइजेशन को तोड़ना
2. प्रत्यक्ष निगरानी द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
3. कंपनियों के बीच स्वस्थ्य कारपोरेट संस्कृति व कारपोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देना
4. अनुचित प्रथा वाली कंपनियों पर दण्ड लगाना (उदा० Idea का विवाद)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(5). हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना

चुनौतियाँ
- CCI के अधिकारियों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप
- राजनेता – अधिकारी – पूंजीपति गठजोड़ द्वारा भ्रष्ट प्रथाओं को बढ़ावा देना
  (उदा. BSNL की 4G नीलामी को रोककर निजी क्षेत्रक को बढ़ावा देना)
- कार्यक्षमता व कौशल संबंधी चुनौतियां
  (उदा. कारपोरेट विशेषज्ञता का अभाव)

आगे की राह
- मानव क्षमता का विकास करना
- CCI को कम्पनियों को दण्ड देने की शक्तियां प्रदान करना
- CCI को कंपनियों से प्रतिस्पर्धा हेतु चार्टर जारी करने का अधिकार

अतः अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापक हस्तक्षेप की संभावना होती है उस दिशा में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग महत्वपूर्ण नियंत्रणकारी संस्था है

8. सरकारी कार्यों में ई-गवर्नेंस के उपयोग से दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार हुआ है। इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा डालने वाली कमियों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

E-governance has brought about greater effectiveness, transparency, and accountability in government functions. Highlight the shortcomings that hinder the improvement of these features. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

ई गवर्नेंस दक्षतापूर्ण सुशासन की दिशा में प्रमुख पहल है। सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा नागरिकों को प्राप्त कराना ही ई गवर्नेंस है।

(उदा० भारत सरकार का ई विजिल, CPGRAMS आदि।)

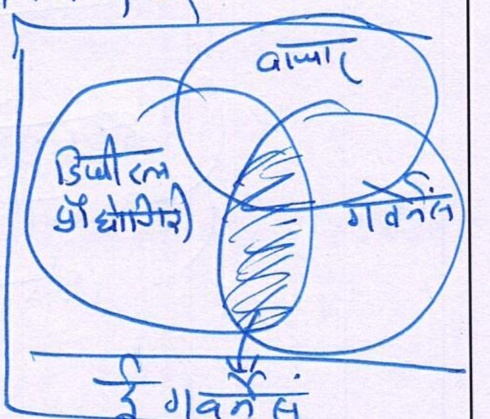

ई गवर्नेंस का महत्व

- शासन में भ्रष्टाचार को कम करने व नियंत्रित करना
- दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता लाने हेतु
- नागरिकों का सशक्तिकरण व भागीदारी मूलक लोकतंत्र की स्थापना
- सेवा आपके द्वार — सामाजिक कल्याण में वृद्धि
- सामाजिक लेखा परीक्षण में वृद्धि
- शिकायत निवारण/समाधान व फीडबैक द्वारा consensus oriented शासन

सरकारी पहलें
- eNAM
- ई ग्राम स्वराज
- भूमि रिकार्ड डिजिटलीकरण

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

बाधाएं

→ डिजिटल डिवाइड व डिजिटल निरक्षरता
(उदा० 1) गांवों में — 44% इंटरनेट
शहरों में — 77% इंटरनेट
2) ग्रामीण आबादी — 18%
शहरी — 57% } डिजिटल साक्षरता)

→ भाषाई चुनौतियां → आधिकतर सेवाओं में अंग्रेजी का प्रभुत्व

→ क्षमताओं का अभाव

लालफीताशाही

शिकायत निवारण व फीडबैक तंत्र का अभाव

आगे की राह

- साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा
- NGO की मदद लेना
- इंटरनेट व डिजीटल अवसंरचना का विस्तार
(उदा० भारत नेट परियोजना, PMवाणी)

अतः भारतीय शासन को नागरिक केंद्रित प्रशासन (2nd ARC) बनाने में लिए ई-गवर्नेंस का व्यापक महत्व है

9. SCO को प्राय: चीन-रूस सहभागिता हेतु एक मंच के रूप में देखा जाता है। संगठन के भीतर भारत के सामरिक हितों के लिये इस साझेदारी के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The SCO is often seen as a platform for Sino-Russian collaboration. Discuss the implications of this partnership for India's strategic interests within the organization. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

SCO का गठन रूस, चीन तथा मध्य एशियाई देशों द्वारा किया गया था। भारत 2017 में इस संगठन का सदस्य बना।

SCO का भारत के सामरिक हितों में महत्व व निहितार्थ -

1) कूटनीतिक - i) सार्क की निष्क्रियता के बाद SCO भारत की कूटनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का व्यापक मंच है

ii) चीन के साथ वार्ता का मंच

iii) रूस के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता

iv) रूस - चीन - पाकिस्तान - ईरान धुरी को बनने से रोकना

2) आर्थिक - i) भारत द्वारा ADB से अपने विकास कार्यों के वित्तयन हेतु काफी ऋण लिया जाता है

ii) भारत को आर्थिक भागीदारी का अतिरिक्त मंच उपलब्ध कराता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

3) राजनैतिक महत्व

i) भारत की लाभ में विस्तार

ii) UNSC में परमानेंट सीट के लिए ईरान व मध्यएशियाई देशों का समर्थन

(4) सांस्कृतिक महत्व → व्यक्ति से व्यक्ति संवाद तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना

(उदा० वाराणसी SCO की सांस्कृतिक राजधानी व बीजींग के बीच सहयोग)

आर्थिक राह

→ व्यापारिक गतिशीलता को बढ़ावा देना

→ रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु साझेदार देशों के बीच करेंसी स्वैप

→ डिडॉलराइजेशन को एजेंडा बनाना

हालांकि SCO में बढ़ती भारत की भागीदारी पश्चिमी देशों व अमेरिका के साथ सहयोगात्मक संबंधों के सामने कड़ी चुनौती पेश करती है किंतु अपनी स्वतंत्र विदेशनीति से भारत अपनी मजबूत सामरिक स्थिति बनाए हुए है।

10. भारतीय प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

The Indian diaspora significantly influences the political and economic landscapes of the United States and European countries. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय प्रवासी दुनिया का सबसे प्रभावी समुदाय है। 30 मिलियन लोग भारत से बाहर प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। हाल ही में अमेरिका व यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को आकार देने में प्रभावी भूमिका देखी गई है।

प्रवासी समुदाय की भूमिका

अमेरिका के साथ →

- आर्थिक →
  - i) भारतीय उत्पादों की अमेरिका में माँग बढ़ रही है
  - ii) भारतीय उत्पादों की ब्रांडिंग करना
  - iii) भारत-अमेरिका के साथ व्यापार आधिशेष में है
  - iv) व्यापार वार्ताओं व समझौतों में
- राजनीतिक → भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी राजनीति में भारतीयों की राजनीतिक हैसियत बढ़ी है, जिसका प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर पड़ा
  (उदा. +) कनाडा मामले में भारत के प्रति अमेरिका का नरम रुख)
  2) हिंद महासागर में भारत-USA साझेदारी (सहयोग)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

यूरोपीय देशों के साथ

- आर्थिक
  - i) ब्राण्ड इंडिया का प्रचार
  - ii) 'जीआई टैग' प्राप्त उत्पादों की निर्यात मांग में बढ़ोत्तरी
  - iii) आर्थिक समझौतों को आकार देना
  - iv) भारतीय कृषि निर्यात 53 मिलियन डॉलर के पार (वाणिज्य मंत्रालय)
- राजनीति
  - i) ब्रिटिश PM ऋषि सुनक के बाद भारतीय प्रवासी समुदाय सशक्त हुआ है
  - ii) ब्रेक्ज़िट के बावजूद भारत का EU से अलग व्यापार समझौता तथा
  - iii) ब्रिटेन से अलग व्यापार समझौता
  - रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीय तटस्थता का प्रभाव

अफ्रीकी राष्ट्र
- सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना
- सहयोग के नये क्षेत्र — पर्यावरण, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

अतः प्रवासी समुदाय यूरोप व अफ्रीका सहित भारतीय राजनीति व विदेशनीति के वाहक बने हुए हैं।

11. भारत का संविधान एक गतिशील, जीवंत दस्तावेज़ है, जिसे प्रगतिशील समाज के साथ अनुकूलन और विकास के लिये अभिकल्पित किया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये।

(250 शब्द) 15

The Constitution of India is a dynamic, living document, designed to adapt and evolve with a progressive society. Illustrate with reference to right to life and personal liberty. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

डॉ० अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष कहा था कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है इसे विश्व के संविधानों को ध्यान बनाया गया है संविधान में लचीले प्रावधान इसको भविष्य की पीढ़ी के अनुरूप बदलने की अनुमति देते है।

भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज के रूप में

1) बदलते सामाजिक महत्वकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 73वां व 74वां संविधान संशोधन

2). शिक्षा को अनिवार्य बनाने हेतु 86वां सं. संशोधन

3). व्यस्क मताधिकार के विस्तार हेतु 61वां संविधान संशोधन (वोट डालने की आयु 21 से घटाकर 18)

4). शैक्षणिक-आर्थिक न्याय हेतु आरक्षण प्रावधान इंद्रा साहनी वाद OBC आरक्षण तथा 103वां संविधान संशोधन EWS आरक्षण

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, जीवन व व्यक्तिगत अधिकार की स्वतंत्रता का विस्तार —

1). मेनका गांधी वाद में — विदेश यात्रा का अधिकार
— रोगाणु मुक्त स्वास्थ्य जीवन का अधिकार
— न्याय की उचित प्रक्रिया

2). हादिया वाद (2017) - विवाह हेतु जीवन साथी चुनना, जीवन का अधिकार

3). पुट्टस्वामी वाद (2017) - निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का भाग है

4). विशाखा दिशा-निर्देश - गरिमापूर्ण जीवन हेतु यौन सुरक्षा जीवन का अधिकार

5). नवतेज सिंह जौहर वाद (2018) धारा 377 का उन्मूलन LGBTQ+ तृतीय लिंग व्यक्तियों को जीवन का अधिकार

6). एम सी मेहता वाद (1982) स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार
जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार

7). अरुणा शानबाग वाद में → इच्छामृत्यु गरिमापूर्ण जीवन का भाग

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अतः भारतीय संविधान जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी मानवीय सुनवाइयों में जीवन के अधिकार को व्यापक व विस्तृत किया है।

12. जेंडर न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों की सहायता से स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

The concept of gender justice is inherently embedded in the Indian Constitution. Explain with the help of relevant constitutional provisions and case laws. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

विश्व बैंक द्वारा जेंडर न्याय को लैंगिक समानता की स्थापना हेतु कल्याण आधारित दृष्टिकोण तथा क्षमता आधारित सशक्तिकरण व अवसरों व सेवाओं तक समान पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने सामाजिक प्रगति हेतु लैंगिक न्याय के विस्तृत प्रावधान किये थे।

संवैधानिक प्रावधान

1) प्रस्तावना - सामाजिक - आर्थिक - राजनैतिक न्याय की संकल्पना तथा स्वतंत्रता व बंधुता

2) मौलिक अधिकार (अनु 13) — कानून के समक्ष समानता, कानून का संरक्षण (अनु 14)
→ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर विभेद का निषेध अनुच्छेद (15 व 16)
→ लोक नियोजन में अवसर की समानता (लैंगिक भेदभाव का निषेध) (16)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार (Art 21)
→ बलात्श्रम व मानव दुर्व्यापार पर रोक (Art 23 व 24)

8) निर्देशक तत्व (DPSP) भाग (IV)

→ आर्थिक स्वतंत्रता व वितरणात्मक न्याय (Art 38)
→ निःशुल्क न्याय तक सार्वभौमिक पहुंच (Art 39 A)
→ प्रसूति, स्वास्थ्य आदि में संरक्षण (Art 42)
आजीविका के अवसर (बिना किसी भेदभाव के Art (42))

9) मौलिक कर्तव्य (51 A) → महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध कार्यों का निषेध

अन्य प्रावधान
- i). Art 334(A) - वयस्क मताधिकार का प्रावधान
- ii) 73वाँ व 74वां संविधान संशोधन 1/3 महिला आरक्षण (PRI में)
- iii) 106वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा व राज्यविधान सभा में महिला आरक्षण

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

जेंडर न्याय संबन्धी निर्णयन विधियां

1) मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय गरिमा हेतु "उचित न्याय की प्रक्रिया" को अपनाया

2). शायराबानो केस में ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित

3). एम एस० शर्मा वाद में महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने उचित माना

4). नवतेज जौहर वाद में धारा 377 का उन्मूलन द्वारा SC ने लैंगिक न्याय तत्त्वा को बढ़ावा दिया

5). विशाखा दिशानिर्देशों में सुप्रीम कोर्ट ने महिला यौन सुरक्षा हेतु कार्यालयों पर ICC का गठन

6) मुद्गलवाद में मंदिर व अन्य धार्मिक संस्थाओं में महिलाओं के प्रवेश को SC ने वैध बताया

अतः भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। समाज में लैंगिक न्याय की स्थापना हेतु व्यापक प्रावधान करता है जिसको सुप्रीमकोर्ट ने विभिन्न निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है

13. भारत में प्रभावी नीतियों को आकार देने और कार्यान्वित करने में नागरिक समाज संगठनों के योगदान का अन्वेषण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Explore the contribution of civil society organizations in shaping and executing effective policies in India.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नागरिक समाज संगठन

ऐसे लोगों को संदर्भित करता है जो शासन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर नीतियों को जनकल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं

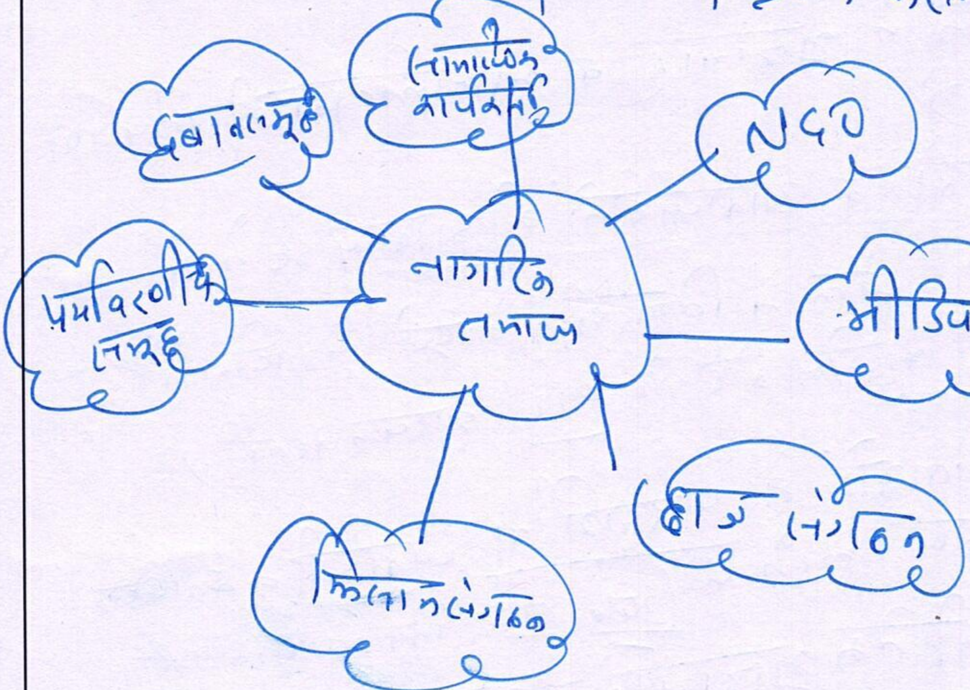

नागरिक समाज का योगदान

1). नीतियों के निर्माण में प्रभावी क्रियान्वयन में

2). भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना में

3)

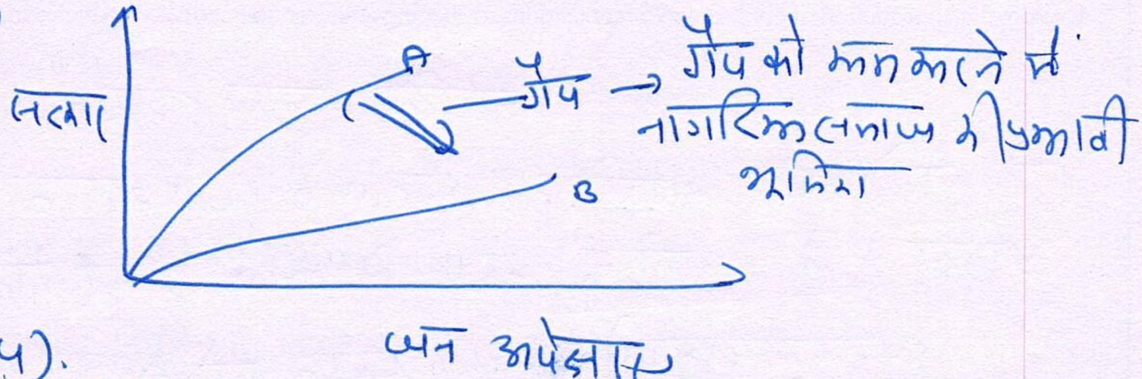

4). शासन में भ्रष्टाचार व लालफीताशाही नियंत्रण में

5). वंचितों व आवासहीनों को आवास उठाने में
(उदा० जेल में विचाराधीन कैदियों के अधिकारों हेतु सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करना)

6). जनसेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही व ईमानदारी तय करने में
(उदा० मजदूर किसान संगठन द्वारा RTI)

7). राजनीतिक भ्रष्टाचार व अपराधीकरण रोकने में
(उदा० एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा चुनावी चंदा उजागर करना)

8). पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करना
(उदा० Collective समूह द्वारा मुम्बई के आरे जंगल तथा छत्तीसगढ़ में हसदेव बचाओ आंदोलन)

9) सामाजिक लेखा परीक्षा
(उदा० मनरेगा में सोशल ऑडिटिंग)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

(1) नागरिक समाज राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ग्रसित हुए हैं

(2) प्रशासनिक दमन व लालफीताशाही का सामना करना पड़ा है

(3) नागरिक समाज वित्त की कमी तथा सक्रिय व समर्पित मानव संसाधन की कमी से जूझ रहा है

(4) कुछ NGO पर विदेशी चंदा लेकर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप (उदा० एमनेस्टी इंटरनेशनल)

आगे की राह

- नागरिकों के बीच जागरूकता व शिक्षा का प्रसार
- ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना
- मेघालय राज्य की तरह सभी योजनाओं व कार्यक्रमों में सामाजिक लेखा परीक्षा का विधिकरण करना

अतः नागरिक समाज अपनी विशेषता व सामाजिक जागरूकता व प्रसार से शासन प्रणाली पर नियंत्रण बनाए रखता है।

14. 'भारतीय न्यायपालिका पुरुष प्रधान है।' इस कथन के आलोक में न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिये। साथ ही सुधारात्मक उपाय संबंधी सुझाव भी प्रदान कीजिये। (250 शब्द) 15

'Indian judiciary is a male dominated affair.' In the light of this statement discuss the issues related to the representation of women in judiciary. Also, suggest remedial measures. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में न्यायालयों में जेंडर न्याय को कमजोर व सीमित रूप में देखा गया है। अधिकांश न्यायालयों में भारत में पुरुष जजों की ही अधिकता है।

राष्ट्रीय विधि आयोग ने न्यायपालिका में जेंडर असमानता से संबंधित आंकड़ों पर चिंता जताई है।

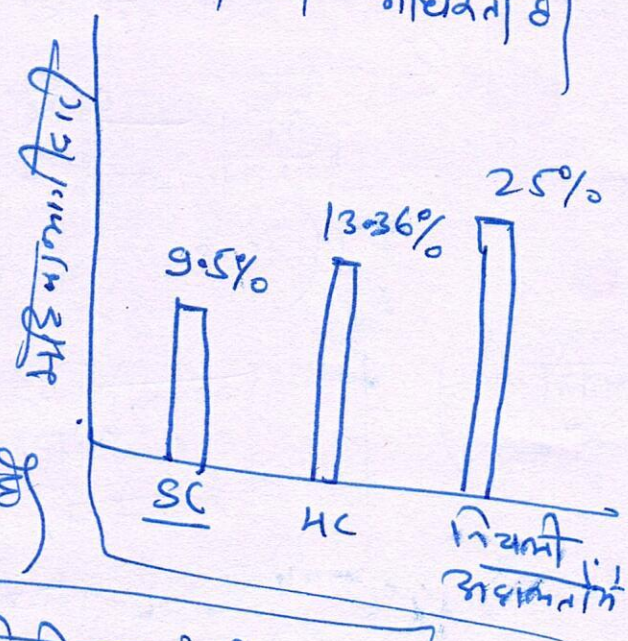

महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधित मुद्दे

1). पितृसत्तात्मक समाज
- महिलाओं के बाहर काम करने पर रोक
- न्यायिक पढ़ाई करने में महिलाओं के समक्ष सामाजिक बाधाएं

2). कार्यस्थलों पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(3). महिला संबंधित कार्यदशाओं का अभाव
(उदा० सुप्रीम कोर्ट में 2% भवन क्रेच सुविधा तथा हाईकोर्टस में 10% भवनों व कार्यालयों में ही क्रेच सुविधा उपलब्ध है)

(4). विधिक पढ़ाई व शादी की उम्र में सामाजिक बाधाएं
(उदा० LLB कोर्स 5 वर्ष, LLM 3 वर्ष तथा अभ्यास करने की उच्च आयु

सुझाव
→ कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा के इंतजाम
→ क्रेच स्थलों का निर्माण करना
→ महिलाओं हेतु विधिक कॉलेजों व विश्वविद्यालयों का निर्माण
→ हाईकोर्ट व निचली अदालतों में महिला (1/3) आरक्षण लागू करना
→ विधिक आयोग व 2nd ARC के अनुसार 'ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस' को लागू करना

अतः भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से महिला अपराधों में कमी आयेगी तथा जेंडर न्याय की अवधारणा में विशेषज्ञता आयेगी।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

15. भारतीय संविधान एकात्मकता का भाव रखता है यद्यपि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों की सुदृढ़ता एवं स्वतंत्रता से समझौता किया है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

Indian Constitution comes with a unitary bias. However, that does not mean that the Constitution makers took anything away from strong and independent states. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में संघीय प्रणाली का विवरण "भारत राज्यों का संघ" के रूप में देता है। ब्रिटिश तथा भारतीय विद्वानों के द्वारा संविधान पर आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान एकात्मक है।

एकात्मक प्रावधान →
- एकल संविधान
- एकल नागरिकता व एकल न्यायपालिका
- अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र के पास
- वित्तीय शक्ति पर केंद्र मजबूत
- राज्यपाल का पद
- अखिल भारतीय सेवाएं
- आपातकालीन प्रावधान

हालांकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संघीय प्रावधान

1. राज्य व केंद्र के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन 7 वीं अनुसूची (समवर्ती, राज्य व केंद्र सूची)
2. अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान (263)
3. लिखित व कठोर संविधान
4. राज्य व केंद्र की विधिक संप्रभुता
5. स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायिक समीक्षा का प्रावधान
6. राज्यसभा की संरचना
7. GST परिषद

चुनौतियाँ

- राज्यपाल के पद का दुरुपयोग
- राष्ट्रपति काल व आपातकाल में राज्य की शक्तियों पर केंद्र का प्रभावी होना
- राज्य सूची पर समवर्ती व केंद्रीय सूची को वरीयता

आगे की राह

- प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाना देना
- संविधान के आधारभूत ढांचे का पालन

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करना (सरकारिया आयोग)
- केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की सिफारिशें लागू करना
  - i) राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित
  - ii) राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लेना
- सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन
  - i) स्टेट वाद vs पंजाब (2023) सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु आरक्षित विधेयकों को अगर विधानसभा दुबारा भेजती है तो राज्यपाल की इस संबन्ध में शक्ति सीमित हो जाती है

अतः ऐसी व्यवस्था भारतीय संघवाद को अविनाशीय बनाने वाला संघवाद कहते हैं। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा व समन्वय द्वारा संवैधानिकता का पालन किया जा सकता है।

16. राज्यसभा की उपेक्षा करने के लिये कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करना संवैधानिक चिंताएँ उत्पन्न करता है। इस संवैधानिक चिंता के समाधान से संबंधित उपायों के सुझाव प्रदान कीजिये। (250 शब्द) 15

Categorization of certain bills as Money Bills to bypass Rajya Sabha raises constitutional concerns. Suggest ways to tackle this constitutional concern. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत का संविधान अनुच्छेद (80) के तहत राज्यसभा तथा अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन करता है। राज्यसभा संसदीय प्रणाली में राज्यों के हितों का संरक्षण करती है।

'धन विधेयक (Art 109)', धन व वित्तीय प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जैसे कर ~~[illegible]~~ का विनियमन बजट खर्च हेतु, संचित निधि के उपयोग हेतु धन का विनियोग करना। धन विधेयक कहलाता है।

हाल के दिनों में राज्यसभा को बाईपास करने हेतु कार्यपालिका द्वारा साधारण विधेयकों को धन विधेयकों के रूप में पारित किया गया है (जैसे आधार बिल, किसानों से संबंधित विधेयक (2020))

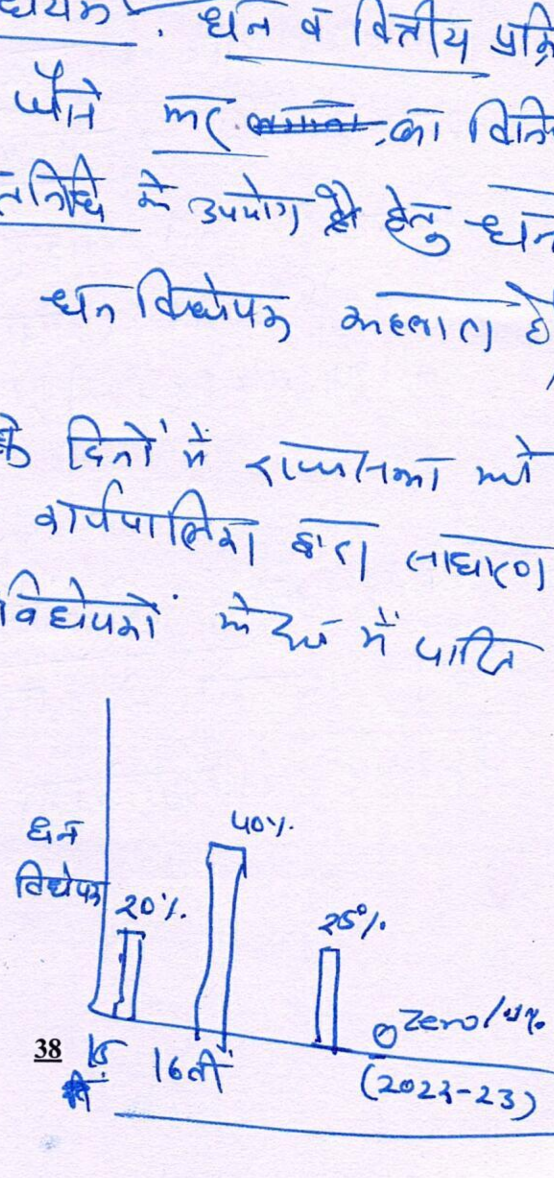

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है वहीं राज्यसभा नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है।

संवैधानिक चिंताए —

→ राज्यों के हितों की अनदेखी

→ व्यापक विश्लेषणता का अभाव

→ 'धन विधेयकों की औचित्यता' का उल्लंघन

→ संसदीय समितियों की अनदेखी

→ व्यापक चर्चा व विमर्श का अभाव

→ अनुच्छेद 108 व 109 का दुरुपयोग

धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं

उपाय व सुझाव —

→ NCRWC तथा विधि आयोग की 223 वीं रिपोर्ट के सुझावों का पालन (उदा० 'धन विधेयक में धन संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना)

→ आधार vs UOI वाद (2020) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा (आधार कार्ड धन विधेयक को उचित ठहराया) तथा स्पीकर हेतु धन विधेयक के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अतः भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की संरचना, लोकसभा से मुकाबले धन विधेयक संबन्धी मामलों में असमान है जिसकी सक्रिय भूमिका तथा सुप्रीमकोर्ट की न्यायिक समीक्षा द्वारा धन विधेयक प्रावधानों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

17. 'भारतीय संविधान अंशतः पश्चिमी देशों के संविधान से गृहित दस्तावेज़ है।' समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द) 15

'Indian Constitution is a bag of borrowings.' Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के आलोचक संविधान पर आरोप लगाते है " कि संविधान उधार का थैला है" इस संबन्ध में डॉ० अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष कहा था मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के संविधानों को छानने के बाद किया गया है।

भारतीय संविधान उधार का थैला

1). भारतीय प्रस्तावना का दर्शन — अमेरिकी संविधान
भाषा — आस्ट्रेलियाई संविधान

2) मौलिक अधिकार → अमेरिकी संविधान

3). राज्य व्यवस्था के प्रावधान — ब्रिटेन के संविधान

4). गवर्नर, न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग — भारतीय गवर्नमेंट एक्ट 1935 से

5). समवर्ती सूची → आस्ट्रेलिया से

6) संघीय व्यवस्था → कनाडा से

7). DPSP → आयरलैण्ड

8) आपात उपबंध — जर्मनी के वाइमर (गणतंत्र)

9) सामाजिक-आर्थिक न्याय — रूस

10). स्वतंत्रता समानता बंधुता — फ्रांस

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान उधार का दस्तावेज नहीं है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता (1947) से पूर्व विश्व के अधिकांश संविधानों का निर्माण हो चुका था।

स्वदेशी संवैधानिक प्रावधान

1) प्रस्तावना में वर्णित न्याय, अवसर, गणतंत्र व धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना

2). विस्तृत व व्यापक मौलिक अधिकार (उदा.
- आरक्षण के प्रावधान
- अस्पृश्यता उन्मूलन (Art 17)
- मानव शोषण व बलात्श्रम के विरुद्ध सुरक्षा (Art 23, 24)
- धार्मिक स्वतंत्रता (25-28)
- अल्पसंख्यकों के अधिकार (29-30)

(3) संविधानवाद तथा संवैधानिक सम्प्रभुता के प्रावधान

(4) DPSP में शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता व पर्यावरणीय न्याय की संकल्पना

(5) संघीय ढांचा – मजबूत केंद्र के साथ अर्द्धसंघात्मक संरचना

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(6) धार्मिक स्वतंत्रताधिकार

(7) पंचायती राज्य में व्यापक प्रावधान

(8) राजभाषा संबंधित अनुसूची व राजभाषा आयोग

अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश की जरूरतों के हिसाब से व्यापक ~~सभी~~ संवैधानिक प्रावधानों का निर्माण किया। भारतीय संविधान की खूबसूरती उसकी जीवंतता है जो समय के साथ लोगों की महत्वकांक्षाओं की पूर्ति करती है।

18. प्रौद्योगिकी के संबंध में जागरूकता का अभाव या अपर्याप्त ज्ञान समाज में डिजिटल विभाजन का कारण बनता है। स्पष्ट कीजिये कि यह भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है। (250 शब्द) 15

Lack of technological awareness or knowledge leads to a digital divide in society. Explain how it adversely effects the education and health sector of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

बढ़ते साइबर स्पेस में डिजिटल ज्ञान महत्त्वपूर्ण है। यह नागरिकों की सुरक्षा व स्वतंत्रता के साथ-साथ राष्ट्र की प्रगति का निर्धारक है।

भारत में असमानता का नया स्रोत उभर रहा है

डिजिटल विभाजन

- ↳ डिजिटल सेवाओं तथा अवसरों पर असमान पहुंच
- ↳ नीति आयोग के अनुसार 40-45% गांवों तक ही इंटरनेट सेवाएं है जबकि शहरों में यह 77% है
- ↳ डिजिटल साक्षरता
  - ग्रामीण - 18%
  - शहरों में 57%

विभाजन बढ़ाने वाले कारक
- → बदलती प्रौद्योगिकी
- → भाषाई बाधाएं
  eg. अंग्रेजी भाषा का एकाधिकार
- ↓ अवसंरचना अभाव

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

शिक्षा प्रभाव

- ASER की रिपोर्ट में ग्रामीण भारत में 13% विद्यार्थियों के पास ही डिजिटल उपकरणों व संसाधनों तक पहुंच है
- → लर्निंग पावर्टी को प्रोत्साहित करता है
  (उदा० शहरों में डिजिटल उपकरणों व गांवों में अवसंरचना अभाव)
- → गांवों में 44% में फाइबर कनेक्टिविटी (आर्थिक सर्वेक्षण 2023)

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- अच्छी गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य से वंचितों व गरीबों को दूर करता है
  (उदा० डिजिटल हेल्थ कार्ड व टेलीमेडिसिन सुविधाओं का अभाव)
- → स्वास्थ्य जोखिम के साथ-साथ साइबर सुरक्षा जोखिम बढ़ता है

सुझाव व आगे की राह

1. डिजिटल सेवाओं का विस्तार ग्रामीण आबादी व गरीबों तक
2. डिजिटल शिक्षा व जागरूकता को बढ़ावा देना
3. भारत नेट परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(5) ग्राम पंचायतों का फाइबराइजेशन व जिला मुख्यालयों से जोड़ना

(6) प्राथमिक व सरकारी स्कूलों में डिजिटल अवसंरचना का विकास करना

(7). टेली हेल्थ व डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा

(8) डिजिटल सेवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना

अतः बढ़ते डिजिटलीकरण के युग में समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु 'लीव नो वन बिहाइन्ड' अवधारणा को अपनाना चाहिए।

drishti | दृष्टि The Vision

19. नाटो का विस्तार एवं अमेरिकी-यूरोपीय सामरिक सहयोग का सुदृढ़ीकरण भारत के हितों को संपुष्ट करता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

India's interests are well-served by NATO's growth and the stronger U.S.-Europe strategic cooperation. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नाटो (उत्तरी अटलांटिक सुरक्षा संधि)

का गठन शीतयुद्ध से निपटने के लिए 1948 में अमेरिका तथा यूरोपीय देशों द्वारा किया गया था।

1) NATO का उद्देश्य → रूस को पश्चिम की ओर विस्तार करने से रोकना।

2) NATO का आदेश → यह एक सुरक्षा संधि है जो "एक पर हमला सब पर हमला" वाले सिद्धांत पर कार्य करता है।

NATO का विस्तार व भारत के हित

1. NATO अपना विस्तार कर रहा है हाल ही में इसमें नार्वे, फिनलैण्ड जैसे देश शामिल हुए हैं।

2) NATO + 2 रणनीति के तहत, अमेरिका नाटो का विस्तार हिंद महासागर में करना चाहता है तथा भारत को उसका हिस्सा बनाना चाहता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत के हित में है →

1. भारत नाटो में शामिल होकर पश्चिम का सहयोग प्राप्त कर सकता है
2. चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तथा सोन कुल्फ आक्रमण की नीति से निपट सकता है
3. हिंद महासागर में भारत की मजबूत स्थिति
4. भारत का रक्षा निर्यात बढ़ सकता है

भारत के पक्ष में नहीं →

1. भारत का रूस जैसे विश्वसनीय सहयोगी को खोने का डर
2. भारत पश्चिम की युद्ध राजनीति में फंस सकता है
3. भारत अनचाहे युद्ध में उलझ सकता है
4. भारत संघर्ष के नये अखाड़े क्षेत्रों में उलझ जायेगा

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

आगे की राह
- गुट निरपेक्ष नीति का पालन करना
- अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की मजबूती बनाए रखना
- हिंद महासागर में अपनी सामरिक व सैन्य स्थिति मजबूत करना

अतः नाटो का विस्तार हिंद महासागर में संघर्षों को जन्म दे सकता है। भारत को इस पक्ष के साथ अपनी विदेश नीति का परिचय देना चाहिए।

20. पर्यावरण संरक्षण एवं समुद्री सुरक्षा संवर्द्धन में IMO (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Role of IMO (International Maritime Organisation) in protecting environment and enhancing maritime safety and security cannot be overstated. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन

UN की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवादों तथा तटीय सीमाओं का निर्धारण व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करता है

पर्यावरण संरक्षण में IMO की भूमिका

① समुद्री प्रदूषण पर विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट जारी करना

② देशों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा ऑवरफिशिंग के मुद्दों को सुलझाना

③ जहाजों के संचालन हेतु पोलर कोड जारी करना

④. समुद्री संसाधनों के दोहन संबंधी

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रतिबद्धताओं को लागू करना
(उदा० 2020 में अपनी रिपोर्ट WTO को सौंपना तथा मत्स्य सब्सिडी के अनुकूल व निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय समन्वय स्थापित करना

⑤ समुद्री कोरलीय जैव विविधता के बचाव हेतु बंदरगाह निपटान व नौसेनायान के दिशा निर्देश तय करना)

सीमाऐं →
① पर्यावरणीय विशेषज्ञता की कमी
② राष्ट्रों के बीच बढ़ते समुद्री विवाद (उदा० भारत-पाक सरक्रीक विवाद)
③ कार्यवाही करने हेतु बाध्यता वाले कानूनों व आदेशों की कमी

आगे की राह →
- विशेषज्ञता पूर्ण मानव संसाधन का विकास
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समन्वय
- पर्यावरणीय संगठनों UNEP WWF UNFCC के साथ मिलकर कार्य करना

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

drishti | दृष्टि The Vision

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)